

नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मंगलवार को 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 2014 में शुरू हुई यह यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं रही, बल्कि भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और प्रशासनिक संस्कृति में व्यापक बदलावों का दौर भी रही है। तीन लगातार लोकसभा चुनावों में जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा राजनीतिक अध्याय लिखा है, जिसकी तुलना अब स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों के लंबे नेतृत्व काल से की जा रही है।

सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जनता का भरोसा बरकरार रखा है। इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सरकार ने विकास और कल्याण योजनाओं को सीधे आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और जनधन खातों जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था में यूपीआई की

उपलब्धियों के बारह वर्ष, चुनौतियों का नया दौर

सफलता ने भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आज भारत में होने वाले डिजिटल लेनदेन का स्तर कई विकसित देशों से भी आगे माना जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विस्तार तथा आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिने जाते हैं। हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी सैन्य सफलताओं ने भी भारत की सामरिक क्षमता को नई पहचान दी है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। राजमार्ग निर्माण की गति में वृद्धि, रेलवे और

हवाई अड्डों का विस्तार तथा रिकॉर्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे निवेश ने विकास को नई दिशा दी है। विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन मान रही हैं। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार सृजन की है। देश की नवसलवादी पर प्रभावी नियंत्रण सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिने जाते हैं। हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी सैन्य सफलताओं ने भी भारत की सामरिक क्षमता को नई पहचान दी है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। राजमार्ग निर्माण की गति में वृद्धि, रेलवे और

पर दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटना और निर्यात क्षमता का विस्तार करना भी आवश्यक होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी सरकार के सामने अपेक्षाओं का दबाव पहले से कहीं अधिक है। लगातार तीन कार्यकालों की सफलता ने जनता की उम्मीदों को बढ़ाया है। अब केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनके परिणामों का मूल्यांकन भी होगा।

12 वर्षों के इस पड़ाव पर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने भारत की दिशा और गति दोनों को प्रभावित किया है। लेकिन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दशक में रोजगार, जल सुरक्षा, कोशल विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि जैसे क्षेत्रों में निर्णायक प्रगति करनी होगी। उपलब्धियों का यह दशक महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आने वाला समय इस बात का परीक्षण करेगा कि भारत अपनी नई आकांक्षाओं को किस हद तक वास्तविकता में बदल पाता है।

दिल्ली डायरी

गिले-शिकवे दूर कर गलबहियां हुए इंडिया समूह के नेता



प्रवेश कुमार मिश्र

लगभग दो वर्षों के अंतर्वर्द्ध के बाद सिकुड़ते जनाधार के साथ इंडिया समूह की बैठक में शामिल हुए क्षेत्रीय क्षेत्रों ने भले ही आपसी बैर भाव को समाप्त कर गलबहियां करते हुए सार्वजनिक मंच से सार्थक संदेश देने का प्रयास किया हो

लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी विभिन्न विषयों को लेकर मतभेद कायम है। चर्चा है कि जिस तरह से लगभग सभी क्षेत्रीय दलों ने अपने सिकुड़ते जनाधार से परेशान होकर कांग्रेसी अगुवाई को अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया है उससे साफ है कि अब क्षेत्रीय दलों को भी भाजपा के खिलाफ किलाबंदी करने के लिए कांग्रेसी हाथ और मजबूत साधियों के साथ की जरूरत है। चर्चा यह भी है कि अब इंडिया समूह में शामिल छोटे दल कांग्रेस को आंख दिखाने के बजाय गलबहियां की रणनीति को महत्व देना आरंभ कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस भी समय व परिस्थिति को भांपकर आपसी विवाद पर पानी डालते हुए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने को तैयार दिख रही है।

डीएमके व आप की अगुवाई में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट

इंडिया समूह बैठक से दूरी बनाकर डीएमके व आप के रणनीतिकारों ने देश के

सामने तीसरे मोर्चे के रूप में एक नया राजनीतिक विकल्प देने की तैयारी आरंभ कर दी है। चर्चा है कि अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस व भाजपा से सीधे टक्कर लेने वाले क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बीच पर्दे के पीछे चर्चा जारी है। इसमें डीएमके, आम आदमी पार्टी, वामदल, टीआरएस यानी बीआरएस, जन सुराज, ओवैसी की पार्टी के अलावा दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के छोटे-छोटे दलों को शामिल करने की बात हो रही है।

मध्यप्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली में भी मंथन

मध्यप्रदेश में तीन सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में चार उम्मीदवार की मौजूदगी के बाद राजनीतिक गुणा-भाग भोपाल के अलावा दिल्ली में बैठे रणनीतिकार भी कर रहे हैं। चर्चा है कि कांग्रेसी रणनीतिकार अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए

बहुस्तरीय रणनीति बनाकर लगातार संपर्क कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सीधे तौर पर कई विधायकों से बात कर चुके हैं। जबकि दूसरी ओर भाजपा अपने दो उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करते हुए तीसरे उम्मीदवार के लिए दस कांग्रेसी विधायकों पर नजर लगाए हुए है। बिहार तर्ज पर मतदान के दौरान अनुपस्थित से लेकर वोट रद्द काराकर अंकगणित के आधार पर बहुत हासिल करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। दिल्ली में इस विषय को लेकर बहुस्तरीय चर्चा भी हो रही है। सबकी नजर कांग्रेसी रणनीतिकारों की अपने कुन्बे को बचाने के तौर-तरीकों पर लगी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सहृदय जनतंत्रवादी



एच. डी. देवेगौड़ा

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि श्री नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मेरी खुशी की वजह यह नहीं है

कि उन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का पंडित जवाहरलाल नेहरू का कीर्तिमान तोड़ दिया। मैं इसलिए खुश हूँ कि उनकी यह उपलब्धि भारत की लोकतांत्रिक विजय के बारे में बहुत कुछ कहती है। भारत ने न केवल अपना अस्तित्व बनाया रखा बल्कि पहले से समृद्ध भी हुआ है। यह एक शानदार सफलता की कहानी है और इस सफलता की कहानी में श्री मोदी का योगदान अद्वितीय और ऐतिहासिक है।

पंडित नेहरू 1952 तक गैर निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 1947 में असाधारण परिस्थितियों में, समान रूप से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों के बीच से चुना गया था। यह महात्मा गांधी का एक तरह का वीटो और जनता पर उनका नैतिक प्रभाव ही था, जिसने प्रधानमंत्री के पद पर पंडित नेहरू के नामांकन को सुनिश्चित किया। 1952 के पहले आम चुनाव में उनके साथ महात्मा का आशीर्वाद और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था। उस समय कांग्रेस पार्टी का

एकाधिकार था। उसे किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि आम चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, लेकिन उनकी मौजूदगी और प्रभाव बहुत कम था। उस समय से लेकर 2014 में जब श्री मोदी पहली बार और फिर 2024 में इस उच्च पद पर पहुंचे, तब तक भारत एक बहुत अलग राष्ट्र बन चुका था। आकार, विविधता, अर्थव्यवस्था और नागरिकों के विकास के मामले में यह लगभग पूरी तरह बदला हुआ था।

यह कहना बहुत विवेकपूर्ण नहीं है कि 2014 या 2024 की तुलना में 1952 में प्रधानमंत्री चुना जाना ज्यादा आसान था। यहां तक कि जब मैं 1996 में प्रधानमंत्री बना, तब तक परिस्थितियां, राजनीतिक मापदंड और मुकाबला पूरी तरह से बदल चुके थे। राष्ट्र अधिक सवाल पूछने वाला, अधिक जागरूक और अधिक परिपक्व हो चुका था। नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के

प्रधानमंत्रियों के पास ऐसा कोई चमकता हुआ आभास नहीं था, जिस पर वे अपना दावा कर सकें, उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई विशेषाधिकार, खानदानी रसूख या किसी का संरक्षण नहीं था। श्री मोदी और स्वयं मेरे मामले में भी, हमारे पास वह सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी भी नहीं थी जो कई अन्य प्रधानमंत्रियों को मिली थी।

मैं ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, मेरा कार्यकाल सिर्फ 11 महीने का था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि श्री मोदी को कौन-सा दैवीय आशीर्वाद मिला है कि वे बिना थके लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं—न तो उनमें थकान का कोई संकेत दिखता है और न ही उन्हें चुनने वाले लोगों में। पद पर रहते हुए उनकी सहनशक्ति और काम करने की क्षमता पंडित नेहरू से बिल्कुल अलग है।

आइए, पंडित नेहरू के समय से लेकर अब तक के कुछ दिलचस्प आँकड़ों पर नज़र डालें। ये उस बड़े बदलाव को दिखाते

हैं जिसका मैंने जिक्र किया है— अगर सिर्फ राजनीतिक मुकाबले की बात करें, तो 1952 के चुनावों में मैदान में सिर्फ 53 पार्टियाँ थीं, जबकि 2024 में श्री मोदी को 2593 राजनीतिक पार्टियों का सामना करना पड़ा। नेहरू के समय में मतदाताओं की संख्या सिर्फ 17 करोड़ थी, जो 2014 तक बढ़कर 83 करोड़ हो गई। भारत की आबादी, जो 1952 में 34 करोड़ थी, आज 146 करोड़ से ज्यादा है।

एक और दिलचस्प बात यह है कि पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में समुदायों की जनसंख्या के आकार या भारत की सांस्कृतिक और जातीय विविधता की झलक नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जब नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे और आखिरी कार्यकाल में थे, तब भी मंत्रिमंडल का गठन काफी असंतुलित लगाता था। इसमें ज्यादातर ऊंची जाति के पुरुष ही शामिल थे। पंडित नेहरू ने काका केलकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें वास्तव में वंचित और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की कोशिश की गई थी।

श्री मोदी वर्तमान में जिस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कर रहे हैं, वह शानदार रूप से विविधताओं से भरा है। इसमें 27 ओबीसी, 10 अनुसूचित जाति (एससी) और 5 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्य हैं।

(लेखक राज्यसभा के सदस्य और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं।)

बिखराव के साथ सिकुड़ गई टीएमसी

चुनावी हार और कुनबाई बिखराव के कारण कभी भाजपा के खिलाफ आक्रामक दिखने वाली टीएमसी इन दिनों अस्तित्व बचाने के संकट में उलझ गई है। जिस तरह से ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ उनके अपने चहेते विधायकों व सांसदों ने मोर्चाबंदी कर अलग राह अपना ली है उससे साफ है कि ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी ने सिर्फ कमजोर हो चुकी है बल्कि विघटन के राह पर भी बहुत आगे निकल गई है। हालांकि इस घटनाक्रम को टीएमसी की आंतरिक राजनीति का परिणाम बताकर भाजपाई नेता अपने को इससे अलग कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस राजनीतिक हालात को शिवसेना के बिखराव की पटकथा से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में टीएमसी सांसदों का भाजपा नेताओं की मौजूदगी में केन्द्रीय मंत्री के आवास पर मिलकर अलग गुट बनाने का निर्णय करना इस उलटफेर के हरेक परत से पदा उठा रहा है।



इस बार कमजोर मानसून के आसार

देशवासी बेसब्री से मानसून की राह देख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही सामान्य से कम मानसून रहने की भविष्यवाणी की है, जो कुल मिलाकर 90 फीसदी बारिश का संकेत है। इसके लिए 'अल नीनो' फेक्टर को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में मानसून अनुकूल रहने से 2024-25 में कृषि में 4.2 प्रतिशत तथा 2025-26 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि खरीफ फसल पर मौसम का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन टंड के दौरान नवंबर से जनवरी तक आने वाली रबी की फसल अल नीनो से प्रभावित होगी। क्योंकि वह मानसून को रोक देगा तथा शीतकाल के दिन भी सीमित हो जाएंगे, जहां तक खाद या उर्वरक का सवाल है, खरीफ मौसम के लिए उसकी मात्रा पर्याप्त बताई जाती है, लेकिन रबी मौसम में उसका अभाव महसूस किया जाएगा। होमज की नाकाबंदी से रुकी रासायनिक खाद की आपूर्ति का असर तब देखा जाएगा। इससे दिसंबर-जनवरी में खाद्यान्न के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इस पर कृषि विशेषज्ञ



बताया जा रहा है कि खरीफ फसल पर मौसम का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन टंड के दौरान नवंबर से जनवरी तक आने वाली रबी की फसल अल नीनो से प्रभावित होगी।

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

पिछले 2 वर्षों में मानसून अनुकूल रहने से 2024-25 में कृषि में 4.2 प्रतिशत तथा 2025-26 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बताया जा रहा है कि खरीफ फसल पर मौसम का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन टंड के दौरान नवंबर से जनवरी तक आने वाली रबी की फसल अल नीनो से प्रभावित होगी।

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा, मका, रागी जैसा मोटा अनाज) दाल तथा तिलहन की पैदावार को जा सकता है। इन फसलों के लिए कम पानी व थोड़ा-सा खाद लगता है। इसके विपरीत धान, गेहूं व गन्ने के लिए अधिक सिंचाई व यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 7.3 मीट्रिक टन दाल आयात की थी तथा 2025-26 में 16.9 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया है। सरकार इस वर्ष मिलेट, दाल व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे

विचार कर रहे हैं। वर्षा और खाद की कमी होने पर मिलेट (ज्वार, बाजरा